

## मुंबई को 659 औषधालयों की जरूरत, एनजीओ की रिपोर्ट का खुलासा



मुंबई मुंबई में सार्वजनिक औषधालयों की भारी कमी है और शहर को कमी को पूरा करने के लिए कम से कम 659 की आवश्यकता है।

एनजीओ प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी एक रिपोर्ट से पता चला है कि सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिमी उपनगरों को हुआ है, जिन्हें कम से कम 315 सार्वजनिक औषधालयों की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 27 फीसदी स्लम आबादी वाले शहर को 133 और डिस्पेंसरियों की जरूरत है, जबकि पूर्वी उपनगरों में 51 फीसदी स्लम आबादी वाले 211 और डिस्पेंसरियों की जरूरत है।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शहरी डिजाइन योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूडीपीएफआई) के मानदंडों के अनुसार, एक सार्वजनिक औषधालय को 15,000 लोगों की आबादी को पूरा करना चाहिए।

प्रजा फाउंडेशन के सीईओ मिलिंद म्हस्के ने कहा, “प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा एक विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण प्रदान करती है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के पहले स्तर के रूप में कार्य करती है और बदले में सरकारी अस्पतालों पर दबाव कम कर सकती है।” “सार्वजनिक औषधालयों की कमी के कारण

निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्ग के लोग निजी स्वास्थ्य सेवा या अन्य निगम द्वारा संचालित तृतीयक देखभाल अस्पतालों तक पहुंच रहे हैं।”

प्रजा द्वारा 2019 के एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में पाया गया कि सबसे कम सामाजिक-आर्थिक वर्गों के 31% लोग निजी स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करते हैं, जबकि 76% अपने घरेलू खर्चों का 10% से अधिक चिकित्सा खर्च पर खर्च करते हैं।

म्हास्के ने कहा, “एक मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की अनुपस्थिति कई कारणों में से एक है, जिसके कारण लोगों को निजी स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप आउट-ऑफ-पॉकेट (ओओपी) लागत में वृद्धि होती है, जो आगे गरीबी की ओर ले जाती है।”

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) में वर्तमान में 187 औषधालय हैं, जिनमें से केवल 12 ही 14 घंटे के लिए सुलभ हैं, उनमें से एक 11 घंटे के लिए सुलभ है, जबकि 174 औषधालय दिन में केवल पांच से सात घंटे के लिए खुले हैं। प्रजा की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में, 115 औषधालय 14 घंटे के लिए खुले थे और 2021 में यह घटकर केवल 12 रह गए। इसने औषधालयों में बढ़ती रिक्तियों पर भी प्रकाश डाला। दिसंबर 2021 तक, रिपोर्ट में कहा गया है कि बीएमसी औषधालयों में चिकित्सा कर्मियों में 21% और पैरामेडिकल स्टाफ में 35% पद रिक्त हैं।

“डी, जी / एस और के / ई वार्ड डिस्पेंसरी जैसे वार्डों में मेडिकल स्टाफ में 50%, 40% और 38% रिक्तियां हैं। महामारी में, हमने देखा है कि कैसे बीएमसी ने युद्धस्तर पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और अनुबंध के माध्यम से और निजी भागीदारी के आधार पर जनशक्ति की खरीद करने में कामयाब रही। बीएमसी ने हमेशा माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है। हमें अपने औषधालयों को मजबूत करने की जरूरत है, और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की जरूरत है, ” म्हास्के ने कहा।

हीलिस इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के निदेशक डॉ मंगेश पेडनेकर ने कहा कि बीएमसी, जिसे कोविड के प्रबंधन का एक समृद्ध अनुभव है, को शहर में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को समग्र रूप से मजबूत करने के लिए रणनीतियों को दोहराना चाहिए। “बीएमसी ने वास्तविक समय के वार्ड-वार डेटा प्रबंधन के साथ, सभी 24 वार्डों में विकेंद्रीकृत कोविड युद्ध कक्ष शुरू करके महामारी को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी प्रबंधन रणनीतियों का प्रदर्शन किया था। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी और नागरिक समाजों और गैर सरकारी संगठनों के बुनियादी ढांचे को जुटाने के माध्यम से किया गया था। मुंबई में समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा ढांचे को मजबूत करने और वास्तविक समय मृत्यु दर और रुग्णता डेटा को बनाए रखने के लिए इसी तरह की रणनीतियों का उपयोग करने की आवश्यकता है।”

सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ता और कार्यकर्ता रवि दुग्गल ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल महत्वपूर्ण है और इसकी अनुपस्थिति के कारण तृतीयक देखभाल केंद्रों में भीड़भाड़ है। “हमारे पास औषधालयों की कमी है। हमें एक छत के नीचे औषधालय और शहरी स्वास्थ्य केंद्र भी बनाने होंगे। एक अच्छी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का अभाव लोगों को निजी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाने के लिए मजबूर कर रहा है, ” उन्होंने कहा।

प्रजा रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, बीएमसी के कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मंगल गोमरे ने कहा कि बीएमसी बजट प्रावधान है ःपूजीगत व्यय के लिए 250 करोड़ और ःइस परियोजना पर राजस्व व्यय के लिए 150 करोड़, जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर शहर की स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना है। बीएमसी ने इनमें से 13 क्लीनिक पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरू करने की योजना बनाई है जिसे बढ़ाकर 70 क्लीनिक किया जाएगा।

“यह शहरी आबादी की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करेगा और हमारे अस्पतालों पर स्वास्थ्य देखभाल के भार को कम करेगा। निजी क्षेत्र में विशेषज्ञ राय लेना मरीजों के लिए महंगा है और साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की सुविधाओं में विशेषज्ञों की उपलब्धता एक चुनौती है। इसलिए, विकेन्द्रीकृत रोगी प्रबंधन प्रदान करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सभी रोगियों के लिए एक विशेषज्ञ उपलब्ध होना समय की आवश्यकता है। इसलिए, बीएमसी एचबीटी पॉलीक्लिनिक्स में अपने परामर्श प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों के साथ जुड़ना चाहती है, ” उसने कहा।

इस बीच, रिपोर्ट से यह भी पता चला कि कुल मधुमेह के मामले 2012 में 26,688 से बढ़कर 2021 में 36,616 हो गए। कुल उच्च रक्तचाप के मामले 2012 में 28,595 से बढ़कर 2021 में 30,011 हो गए।

Link : <https://bhartiyadainikpatrika.com/mumbai-needs-659-dispensaries-reveals-ngo-report-101657639436094-html/>